**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3926**

**(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**मनरेगा के लिए निधि**

**3926. श्री यूसुफ पठान:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए वित्तपोषण का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार किस प्रकार इन योजनाओं का समर्थन करने की योजना बना रही है जो ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करती है?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**

**(श्री कमलेश पासवान)**

**(क) और (ख):** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के लिए 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है , जो स्थापना के बाद से बजट अनुमान (बीई) चरण में योजना के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करते हुए इस आवंटन को 86,000 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है।

चूंकि महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है , इसलिए केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस मांग की गहन निगरानी करता है और जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को पूरा करने के लिए जब कभी आवश्यक होता है , वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

*****